18 जनवरी से दो फरवरी 2020 तक राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल की वजह से यह फैसला किया गया है। राष्ट्रपति भवन प्रांगण में सैन्य परंपरा के तहत शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति के गार्ड की अदला-बदली होती है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 12 जनवरी 2020

न्यूज गैलरी

ढींडसा पिता-पुत्र शिरोमणि अकाली दल से निलंबित

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल ने बगावत करने वाले राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा और उनके विधायक पुत्र परमिंदर सिंह ढींडसा को निलंबित कर दिया है। शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कोर कमेटी की बैठक में दोनों को चार्जशीट देकर जवाब मांगे जाने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि ढींडसा पिता-पुत्र ने पार्टी में तानाशाही का आरोप लगाते हुए सुखबीर बादल की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा किया था। पार्टी प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा के अनुसार कोर कमेटी दोनों नेताओं को चार्जशीट देकर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक में संगरूर के पर्यवेक्षक और पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने बताया कि ढींडसा पिता-पुत्र की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण संगरूर में पार्टी की जिला इकाई ने एकमत से दोनों को पार्टी से निष्कासित किए जाने की सिफारिश की है। (राब्यू)

नगरीय निकाय में भाजपा की हार के बाद छाए भूपेश बघेल

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में भाजपा का सूपड़ा साफ करने के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गया है। प्रदेश के सभी दस नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बनने के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने ट्वीट करके भूपेश बघेल को बधाई दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहित अन्य नेताओं ने ट्वीट करके छत्तीसगढ़ की जीत को राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का काम किया। दरअसल, देशभर में मोदी लहर के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मोदी लहर में जब उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश में सिर्फ एक सांसद की जीत हुई, जबकि छत्तीसगढ़ से दो सांसद लोकसभा पहुंचे। (नईदुनिया)

'गुरबाणी प्रसारण के एकाधिकार पर सुखबीर को तलब करें'

चंडीगढ़ : पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने श्री हरिमंदिर साहब से गुरबाणी प्रसारण पर एक टीवी चैनल के एकाधिकार को गुरु साहिबान के सिद्धांतों के उलट बताया है। उन्होंने पीटीसी चैनल की तरफ से श्री दरबार साहिब से जारी होने वाले पवित्र हुक्मनामे को फेसबुक पर शेयर करने की भी निंदा की है। जाखड़ ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से सुखबीर बादल को गुरु मर्यादा का अपमान करने के आरोप में श्री अकाल तख्त साहिब पर तलब करने व कार्रवाई की मांग की है। जाखड़ ने कहा कि सुखबीर पार्टी के अध्यक्ष हैं और चैनल के मालिक भी हैं। एसजीपीसी का अध्यक्ष भी वही मनोनीत करते हैं। ऐसे में आपसी हितों के टकराव में सुखबीर से यह उम्मीद करना बेमानी है कि वह पंथक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। इसलिए जरूरी है कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार इस मुद्दे पर दखल दें और गुरबाणी तक सब की पहुंच बनाने के लिए कार्रवाई करें। (राब्यू)

'शराब उप-दुकानों में गन्ने का रस, दूध, मक्खन मिलेगा'

भोपाल : मध्य प्रदेश में शराब की उप-दुकान खोलने के फैसले पर सियासत और गर्मा गई है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के 150 वें जयंती वर्ष में मध्य प्रदेश को नशे में ना डुबोएं। मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र का जवाब देने के लिए धन्यवाद देने के साथ ही शिवराज ने कहा, 'उनका जवाब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर नई शराब नीति का विरोध किया। मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि शराब की उप-दुकानों में क्या गन्ने का रस, दूध, पनीर, मक्खन बिकेगा?' (नईदुनिया)

जेपी नड्डा होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

मिलेगी कमान ▶ 20 जनवरी को ताजपोशी संभव, अभी कार्यकारी अध्यक्ष की निभा रहे भूमिका

अगले तीन साल तक दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष होंगे

नीलू रंजन, नई दिल्ली

जेपी नड्डा। फाइल

भाजपा के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथ में ही अब पार्टी की औपचारिक कमान सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। पटना में जन्मे नड्डा को इसी महीने 19 या 20 तारीख को विधिवत भाजपा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इसके बाद वह अगले तीन साल तक दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष होंगे।

अमित शाह का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी संभालने को कहा गया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 50 करोड़ गरीबों के लिए पांच लाख रुपये सालाना तक मुफ्त इलाज की आयुष्मान भारत और बच्चों के टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने वाले जेपी नड्डा को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तभी साफ हो गया था कि उन्हें भाजपा संगठन की कमान सौंपी जाएगी। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पार्टी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इसके बाद पार्टी संविधान के अनुसार पार्टी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई जो 20 जनवरी को पूरी हो जाएगी।

दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के आधे से अधिक राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है। इसके बाद राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जिला व संसदीय स्तर पर प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। बताया जा रहा है कि 18 जनवरी तक आधे से अधिक राज्यों के पार्टी अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा और जिला या संसदीय प्रतिनिधियों का भी चयन कर लिया जाएगा। वैसे तो पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए 19 या 20 जनवरी में से एक तारीख तय की है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया 20 जनवरी को होने की संभावना ज्यादा है।

जेपी आंदोलन से रखा था छात्र राजनीति में कदम

▶ 1993 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद भाजपा विधायक दल के नेता बने थे

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : देश का छोटा सा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जेपी नड्डा अब विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा की कमान संभालेंगे। नड्डा ने जेपी आंदोलन से छात्र राजनीति में कदम रखा था। उन्हें अत्यंत मृदुभाषी और संयम रखने वाला नेता माना जाता है।

बिलासपुर जिले के मूल निवासी जगत प्रकाश नड्डा 1993 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद भाजपा विधायक दल के नेता बने थे। 1998 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नड्डा ने मुख्यमंत्री बनने से इन्कार कर दिया था और प्रेम कुमार धूमल के नाम का प्रस्ताव किया था। 2009 में मंत्री पद छोड़कर नड्डा संगठन की राह हो लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा की संगठनात्मक दक्षता से परिचित थे। इसी कारण मोदी सरकार में 2014 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहने के साथ वह पार्टी महासचिव भी रहे। भाजपा संसदीय बोर्ड का सचिव पद भी नड्डा के पास रहा। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जेपी नड्डा 1977 से 1979 तक रांची में रहे हैं। उनके पिता एनएल नड्डा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे।

नड्डा के राजनीति सफर की शुरुआत साल 1975 में जेपी आंदोलन से हुई थी। देश के सबसे बड़े आंदोलनों में गिने जाने वाले इस आंदोलन में नड्डा ने भी भाग लिया था। इसके बाद वह बिहार भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में शामिल हो गए थे। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई की। 1983 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव (एससीए) में वह विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में वह आगे बढ़ते गए और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है।

शाह रखेंगे दूसरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की आधारशिला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ आइआइटी और आइआइएम की तर्ज पर कौशल विकास के लिए खोले जाएंगे तीन इंस्टीट्यूट

▶ मुंबई और अहमदाबाद के बाद कानपुर में तीसरा संस्थान खोलने की तैयारी

अमित शाह। फाइल

आइआइएम और आइआइटी की तर्ज पर युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रस्तावित दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स अहमदाबाद में खोला जाएगा। अगले बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी आधारशिला रखेंगे। इससे पहले कौशल विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने मुंबई में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की आधारशिला रखी थी। जल्द ही कानपुर में ऐसे तीसरे इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अगले एक-डेढ़ साल के भीतर तीनों संस्थान बनकर तैयार हो जाएंगे। कोशिश है कि इनमें 2021-22 से कौशल विकास के प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाए। सरकार की मूल योजना देशभर में उच्च स्तर के छह संस्थान खोलने की है।

कौशल विकास मंत्रालय के अनुसार, आइआइएम और आइआइटी की तर्ज पर कौशल विकास के लिए बनने वाले उच्च स्तरीय संस्थानों को पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्योग जगत की अत्याधुनिक जरूरतों के अनुसार विश्वस्तरीय प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल आइटीआइ जैसी संस्थाएं युवाओं के कौशल विकास का प्रशिक्षण देती हैं। लेकिन, उच्च गुणवत्ता के कौशल विकास के लिए ये अपर्याप्त हैं, जबकि उच्च प्रशिक्षित कामगारों की मांग बढ़ती जा रही है। जाहिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स भविष्य में इस कमी को पूरी कर सकेगा। इनमें ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर टेक्नोलॉजी और ऊर्जा संरक्षण के विशेष पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में ही विभिन्न उद्योगों में इन विषयों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ेगी।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन संस्थानों में सीधे 12वीं पढ़ने के बाद नामांकन की सुविधा होगी। इसके साथ ही आइटीआइ के प्रशिक्षित छात्रों को भी यहां अपने कौशल को और अधिक विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आइटीआइ के पाठ्यक्रम में जरूरी बदलाव करने पर काम चल रहा है।

बंगाल के राज्यपाल के तौर पर धनखड़ सबसे उपयुक्त : स्वामी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बंगाल के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।

स्वामी ने यह बात विराट हिंदुस्तान संगम के बंगाल चैप्टर द्वारा कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में कही। राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। स्वामी ने कहा कि राज्यपाल धनखड़ बहुत ही सुलझे इंसान व संविधान के जानकार हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के राज्यपाल के तौर पर वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जब से धनखड़ ने राज्यपाल पद की शपथ ली है, उसके बाद से बंगाल सरकार के साथ उनका लगातार टकराव जारी है। धनखड़ बराबर ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित राज्य के अन्य मंत्रियों की ओर से भी राज्यपाल पर लगातार हमला जारी है। इस बीच वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की पहल भी कर रहे हैं।

पीएम से मिल सोरेन ने उठाई ट्राइबल विवि की मांग

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली मुलाकात में उन्होंने राज्य के विकास में केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई और झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री से मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने राज्य के विकास में केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई है। प्रधानमंत्री ने भी समन्वय पर जोर देते हुए भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी पर भी पीएम ने सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है।

हेमंत ने कहा कि वह राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री से मिलेंगे और राज्य को केंद्र से मिलने वाले अनुदान आदि पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दीं, तो हेमंत ने प्रधानमंत्री को शॉल ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सोरेन ने उन्हें शाल और प्रतीक चिह्न भेंट किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सोरेन पहली बार दिल्ली आए थे। प्रेट्र

ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बहरागोड़ा और गुमला में खोलने पर है विवाद : झारखंड की पिछली सरकार भी राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार कर रही थी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पिछले वर्ष 17 अगस्त को आयोजित बैठक में बहरागोड़ा में इसके खोलने की स्वीकृति यह कहते हुए दी थी कि बहरागोड़ा ओडिशा और बंगाल से भी नजदीक है। इससे इन राज्यों के भी छात्र यहां पढ़ने आ सकते हैं। बाकायदा यूनिवर्सिटी के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय को जमीन चिह्नित करने का भी निर्देश दिया था। इससे पहले सरकार गुमला में इस विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाह रही थी। केंद्र से ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत इसके लिए अनुदान भी मिल सकता है।

▶ झारखंड के सीएम ने राज्य से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री से की चर्चा

खुल सकती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की शाखा

वैसे तो मुख्यमंत्री ने नए ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग की है, लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र की पूर्व में राज्य सरकार से जो विमर्श हुआ है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की शाखा भी झारखंड में खुल सकती है।

बाबूलाल के रुख को लेकर झाविमो में बेचैनी

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के भाजपा में विलय की बात पर बाबूलाल मरांडी के रुख को लेकर की पार्टी में बेचैनी है। बेचैनी इसलिए, क्योंकि बाबूलाल अबतक भाजपा के विरुद्ध बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुप्पी साध ली है।

पार्टी के शेष दो विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की में भी बाबूलाल के इस स्टैंड को लेकर नाराजगी है। पूछने पर प्रदीप यादव ने दो टूक कहा कि बाबूलाल की बातें बाबूलाल ही जानें। अलबत्ता, पार्टी विलय की दिशा में है, लेकिन मैं वहीं हूं जहां था और विलय दो तिहाई विधायकों की रजामंदी से ही संभव है। मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की के सुर भी इस मसले पर बाबूलाल के खिलाफ है। विलय की बात पर बंधु ने स्पष्ट कहा कि कहीं न कहीं आग है, तब ही तो धुआं उठ रहा है। उन्होंने कहा कि विलय की बात को लेकर पार्टी असमंजस में है। उन्हें भरोसा है कि भाजपा ने पार्टी का जितना अहित किया है, बाबूलाल भाजपा में नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं, तो यह अच्छा नहीं होगा। इस मामले में झाविमो सुप्रीमो को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए।

रघुवर ने दिल्ली आवास छोड़ा नहीं लेकिन हट गई उनकी नेम प्लेट

राज्य ब्यूरो, रांची

रघुवर दास। फाइल

मुख्यमंत्री बदलते ही सरकारी अमला नए हाकिम की सेवा में इस कदर जुट जाता है कि कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को दिल्ली में मथुरा रोड स्थित मिले आवास के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। यह आवास अभी भी रघुवर दास के नाम पर आवंटित है, लेकिन नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को देखते हुए इस आवास को न सिर्फ दुरुस्त कर दिया गया, बल्कि पुराने मुख्यमंत्री की नेम प्लेट तक हटा दी गई। मुख्यमंत्री के शिड्यूल में भी यह जारी किया गया कि था कि वे मथुरा रोड स्थित आवास में ही रुकेंगे। वह तो गनीमत रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस आवास में न जाकर झारखंड भवन में रुके। इस पूरे प्रकरण पर झारखंड सरकार के दिल्ली में बैठे अफसरों की लापरवाही उजागर हुई है।

रघुवर दास ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास चुनाव में हार के कुछ दिनों बाद ही छोड़ दिया था, लेकिन दिल्ली मथुरा रोड स्थित आवास उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। नियमानुसार वे एक माह तक इस आवास को अपने पास रख सकते हैं और यह अवधि 28 जनवरी को समाप्त होगी। यदि भारत सरकार चाहे तो इस अवधि में विस्तार भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि रघुवर ने तीन माह के एक्सटेंशन के लिए आवेदन भी दिया है, जिस पर भारत सरकार की कमेटी विचार कर रही है। तकनीकी रूप से रघुवर जब मथुरा रोड स्थित आवास सरेंडर करेंगे, तभी नए मुख्यमंत्री को आवास एलॉट होगा। यह भी संभव है कि सरकार उन्हें कोई और आवास आवंटित कर दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक दो बार दिल्ली गए हैं, लेकिन वे मथुरा रोड स्थित आवास में अब तक रुके नहीं हैं।

कश्मीर में पीएसए हटते ही 26 लोगों की रिहाई शुरू

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ **बदलते हालात**

▶ रिहा होने वालों में कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन नजीर अहमद रोंगा भी शामिल

कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन नजीर अहमद रोंगा समेत 26 लोगों से जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए हटने के बाद इनकी रिहाई शुरू हो गई है। इन सभी से शुक्रवार को पीएसए हटाने का फैसला हुआ था। ये सभी जम्मू-कश्मीर समेत देश के अन्य राज्यों की जेलों में कैद थे। इनमें से दस लोग, जो श्रीनगर में कैद थे, को शुक्रवार को ही रिहा कर दिया गया था। अन्य में कुछ को शनिवार को छोड़ दिया गया। वहीं, बचे हुए लोगों अगले दो दिन में छोड़ दिया जाएगा।

रोंगा को उदारवादी हुर्रियत कांफ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर का भी करीबी माना जाता है। अलबत्ता, पीएसए के तहत बंदी बनाकर रखे गए नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला की रिहाई पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के मद्देनजर घाटी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लगभग पांच हजार लोगों को हिरासत में लिया था। इन लोगों को आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए रिहा किया जा रहा है। पीएसए से मुक्त होने वाले इन 26 लोगों में से कई विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं। इनके अलावा कुछ पर वनों की अवैध कटाई में लिप्त होने का भी आरोप था। जिन 26 लोगों को पीएसए से मुक्त किया गया है, उनमें सिर्फ एक नजीर अहमद रोंगा ही श्रीनगर के रहने वाले हैं। उत्तरी कश्मीर में जिला बारामुला के रहने वाले 11 लोगों अब्दुल सलाम राथर, तनवीर अहमद बट, मोहम्मद उमर डार, मुदस्सर अहमद तांत्रे, मोहम्मद इमरान डार, मुजफ्फर अहमद डार, शब्बीर अहमद लोन, फैयाज अहमद नायकू, शहनवाज अहमद डार और जहूर अहमद मीर शामिल हैं। दक्षिण कश्मीर में जिला पुलवामा के सात लोगों रौफ अहमद डार, रमीज अहमद हज्जाम, शौकत अहमद शाह, शब्बीर अहमद वानी, उमर गुल, आदिल अहमद लोन और रफीक अहमद बट को पीएसए से रिहाई मिली है। दक्षिण कश्मीर में ही अनंतनाग जिले के मोहम्मद आरिफ लोन, इश्फाक अहमद गनई, मुदस्सर मकबूल तेली समेत तीन लोगों को और जिला कुलगाम के शब्बीर अहमद बट, नवाज अहमद हारु और सद्दाम हुसैन हारु समेत तीन लोगों पर लगा पीएसए हटाया गया है। जिला शोपियां के जावेद अहमद कलास को भी पीएसए से रिहा करने का फैसला लिया गया है।

जल्द बनेगा नया राजनीतिक संगठन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर की सियासत में हलचल पैदा करने वाले पीडीपी से निष्कासित पूर्व वित्त मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी ने शनिवार को दावा किया कि जल्द ही एक नया राजनीतिक संगठन सबके सामने होगा। बुखारी ने कहा कि पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरी बातचीत हुई है। कोई किसी का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए तीसरे मोर्चे में जाने का सवाल ही नहीं। अगर हुआ तो एक नया राजनीतिक संगठन होगा। इसमें पीडीपी के एक दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के अलावा कांग्रेस व नेशनल कांफ्रेंस के चेहरे भी होंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के लिए अब हंगामा करने की जरूरत नहीं है, यह वापस नहीं आने वाला, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अल्ताफ बुखारी को गत वर्ष ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में संगठन से निष्कासित कर दिया था। वह बीते तीन माह से जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा की सियासी गतिविधियों को बहाल करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। गत दिनों उन्होंने पीडीपी के छह पूर्व विधायकों और एक पूर्व एमएलसी के साथ उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के हालात का जायजा लेने आए विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भी उनके साथ पीडीपी के कई पूर्व विधायक थे।

विवाद के आसार

केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्री पासवान ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर को लिखा पत्र, पिछले साल भी केंद्र ने दी थी चेतावनी लेकिन आढ़तियों ने किया था विरोध

किसानों को सीधी अदायगी का मुद्दा फिर गरमाएगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

अप्रैल में शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को उनकी फसल की सीधी अदायगी का मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक बार फिर से ताकीद किया है कि इस साल अगर उसने किसानों की फसल की अदायगी सीधी न की तो प्रशासनिक चार्ज नहीं दिए जाएंगे। कुल मिलाकर गेहूं व धान के लिए केंद्र से मिलने वाली कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) का मामला लटकेगा। केंद्र ने पिछले साल भी राज्य सरकार को यह चेतावनी दी थी, लेकिन आढ़तियों के विरोध के कारण एक सीजन की मोहलत दे दी गई थी जो अप्रैल में पूरी हो जाएगी।

केंद्र सरकार ने सभी खरीद एजेंसियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि हर किसान का खाता नंबर उसे भेजा जाए ताकि पता चल सके कि किसान ने कितनी फसल बेची थी। उसके खाते में उतनी पेमेंट गई या नहीं। यही नहीं, आढ़तियों को दिए जाने वाला कमीशन, लेबर को दी जाने वाली पेमेंट का भी इसी तरह से अलग-अलग हिसाब दिया जाए। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम बिलास पासवान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर 2020-21 के सीजन में सीधी अदायगी को यकीनी बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा और छूट अब नहीं दी जा सकती।

उधर, केंद्र सरकार के इस पत्र के बाद पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने किसानों को सीधी अदायगी का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। पिछले सीजन के दौरान जारी पत्र का आढ़तियों ने विरोध किया था। लंबी मशक्कत के बाद आढ़ती इस बात पर राजी हो गए थे कि किसानों को उनकी फसल की पूरी अदायगी चेक के जरिए कर देंगे। खरीद एजेंसियों ने 33 फीसद किसानों को सीधी अदायगी भी की जिसकी राशि लगभग 9600 करोड़ रुपये बनती है। शेष राशि आढ़तियों के जरिये ही दी गई।

केंद्र से अब छूट की उम्मीद नहीं : पंजाब में लगभग 16.5 लाख किसान हैं जिनकी फसल मंडियों में बिकने के लिए आती है। फूड एंड सप्लाई विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि केंद्र से अब छूट की उम्मीद नहीं है।

आढ़तियों व किसानों के रिश्ते प्रभावित होंगे

दूसरी तरफ आढ़ती इस बात का विरोध कर रहे हैं। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालरा ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से आढ़तियों और किसानों के बीच सालों से बने रिश्ते प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मंडी बोर्ड के एक्ट में भी संशोधन करना होगा।

किसान संगठन भी पक्ष में नहीं

किसानों के कुछ संगठन भी सीधी अदायगी के पक्ष में नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि ऐसा करने से सालों से बना हुआ सिस्टम हिलेगा।

फिर से रविंद्र रैना बनेंगे जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

राब्यू, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से चल रही जद्दोजेहद पर 15 जनवरी को विराम लग जाएगा। 15 जनवरी को प्रदेश भाजपा को अध्यक्ष मिल जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र रैना ही अगले तीन वर्ष के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए आरएसएस और भाजपा के कई नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक कर जम्मू कश्मीर में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबी चर्चा की है। चर्चा में रविंद्र रैना के नाम पर ही सबसे ज्यादा मंथन हुआ है, ऐसे में रैना का अगले तीन वर्ष के लिए फिर से अध्यक्ष चुना जाना तय माना रहा है।

हिमाचल के विधायक विनोद बोले, नहीं हुआ जातिगत भेदभाव

जागरण संवाददाता, मंडी

▶ डीएसपी मुख्यालय मंडी कर्ण गुलेरिया ने दर्ज किए विनोद कुमार के बयान

नाचन के विधायक विनोद कुमार ने मंडी पुलिस को साफ कह दिया है कि उन्हें और सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल को किसी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका गया है। विनोद कुमार ने कहा कि न तो दोनों को किसी ने रोका और न उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव हुआ है।

एससीएसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सात जनवरी को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। चर्चा का जवाब देते हुए डॉ. राजीव सैजल ने कहा था कि मंडी जिले के नाचन हलके के दौरे के दौरान वहां के विधायक विनोद कुमार व उन्हें एक मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था। हालांकि डॉ. राजीव सैजल ने मंदिर का नाम नहीं बताया था। विधानसभा में दिए बयान के बाद मामला तूल पकड़ गया था। कई नेताओं व संगठनों के पदाधिकारियों ने भेदभाव को लेकर कड़ी निंदा की थी। नाचन हलके के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र राणा ने भी डॉ. सैजल के आरोपों को सिरे से नकार दिया था। दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के संयोजक चमन राही व वाल्मीकि समाज सुधार समिति के संस्थापक चंद्रवीर कागरा ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक मंडी गुरदेव शर्मा को शिकायत पत्र सौंप आरोपितों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने वि